कोरोना काल में लॉकडाउन और प्रतिबंधों का सीधा असर उद्यमों और बाजारों पर पड़ा। दोनों अब उस बुरे दौर से उबर चुके हैं। बाजार में पैसा लौटने से उद्यमियों, कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। इनके विकास से जुड़े विभाग और अधिकारी भी इसे एक अच्छे संकेत के रूप में ले रहे हैं। ऐसे में निवेश बढ़ाने और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना पर काम शुरू हुआ है। ऐसा पहली बार है जब लखनऊ में निजी क्षेत्र का औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी है। पेश है अतुल भारद्वाज की रिपोर्ट...

बाजार में पैसा वापस आने से उद्यमियों और कारोबारियों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

उद्योग जगत ने पकड़ी रफ्तार

2022 में उद्योगों की हालत सुधरी तो बैंकों में भी पैसा वापस आने लगा

तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे के बड़े-बड़े पार्ट्स के कारखाने हैं।

2023 में करीब 600 यूनिट लगाने का लक्ष्य है जिला प्रशासन और विकास भवन का

जेट्टी पुल में इस्तेमाल होने वाली टंकियां भी तालकटोरा में बनती हैं।

इन्वेस्टर्स समिट में 5000 करोड़ के निवेश का रखा है लक्ष्य

फरवरी में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट के लिए लखनऊ ने भी दम भरा है। उद्योग लगाने या उनके विस्तार में करीब 5000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसमें रखा क्षेत्र के अलावा निर्माण इकाइयां, सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट शामिल हैं। इसके लिए उद्यमियों ने जिला उद्योग केंद्र में अपने प्रस्ताव भी दिए हैं। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान अनुबंध किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के तुरंत बाद इतना अधिक सकारात्मक रुख इंडस्ट्री की तरफ से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उद्योग खुद को बेहतर स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे में निवेश भी कराने में सहूलियत होगी।

औद्योगिक जिले की तरफ बढ़े कदम

औद्योगिक जिले की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जानी हैं। मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल के मुताबिक इस योजना में बख्शी का तालाब में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई है। पं. दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के अलावा बैंकों से आर्थिक सहायता दिलाकर इन्हें खड़ा किया जा रहा है। इन छोटी-छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में केला चिप्स से लेकर दोना-पत्तल और रेशा बनाने तक का काम हो रहा है। केला चिप्स बनाने की तीन यूनिट चक पृथ्वीपुर गांव में लगी हैं। वहीं, दोना पत्तल का काम चकपृथ्वीपुर, खेसराखां में हो रहा है। रेशा बनाने का काम बाहरगांव और चकपृथ्वीपुर में शुरू कराया गया है। इसे अब पूरे लखनऊ में ले जाया जा रहा है। जिला प्रशासन और विकास भवन ने साल 2023 में करीब 600 यूनिटें लगाने का लक्ष्य रखा है।

1000 एकड़ जमीन में बनेगा निजी औद्योगिक पार्क

उद्योगों में विस्तार और जमीन की कमी को पूरा करने के लिए पहली बार लखनऊ में निजी औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन और जिला उद्योग केंद्र के प्रयास से कानपुर रोड पर जमीन चिह्नित करने का काम शुरू हो गया है। वहीं, उद्योग समूहों से भी सहमति बनाई गई है। इसके लिए अब इन्वेस्टर्स समिट में अनुबंध भी किया जाना है। करीब 1000 एकड़ जमीन में यह निजी औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। इसमें इंडस्ट्री चैंबर्स के अलावा उद्यमियों के क्लस्टर को भी शामिल होने का मौका दिया गया है। इसमें उद्यमी सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ विकसित भूखंड ले पाएंगे। प्रशासन यहां जरूरी विकास कार्य सुनिश्चित कराएगा।

कर्ज वापसी का अनुपात सुधरा

वर्ष 2020-21 में कोविड संक्रमण के भयावह होने के बीच लॉकडाउन और इसके बाद चले प्रतिबंधों ने बाजार को बुरी तरह से प्रभावित किया। आलम यह हो गया कि बैंकों से जो पैसा कारोबारियों और उद्यमियों ने कर्ज के रूप में लिया उसकी अदायगी तक मुश्किल हो गई। जिले की लीड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक कर्ज वापसी की वसूली 20 फीसदी तक गिर गई थी। 2022 में उद्योगों की हालत सुधरी तो बैंकों में भी पैसा वापस लौटने लगा। साल के अंत तक यह अनुपात सुधरकर 48 फीसदी हो गया। इसे और अधिक सुधारने के लिए बैंकों को कहा गया है। खुद प्रशासन ने भी उद्यमियों से जब इसके लिए बात की तो अधिकतर लोगों ने पुराना बकाया भी इसी वित्तीय वर्ष में चुका देने की बात कही है। ऐसे में मौजूदा वित्तीय वर्ष में किस्तों के रूप में आने वाले यह कर्ज अदायगी 80 फीसदी तक पहुंच सकती है। इसे वित्तीय संस्थानों की सेहत ठीक हो पाएगी।

ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर काम शुरू

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की यूनिट लगाने का फैसला वर्ष 2021 में हुआ। इसके लिए जमीन भी शासन के निर्देश पर सरोजनीनगर तहसील के भटगांव में मिल गई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का काम शुरू हो गया है। साल 2023 के अंत तक इसके निर्माण का काम पूरा करने की तैयारी है। इसके बाद यहां ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कानपुर रोड पर ट्रांसपोर्टनगर मेट्रो स्टेशन के पास रक्षा क्षेत्र के उत्पादों की टेस्टिंग यूनिट और लैब भी बनाई जानी है। इसके लिए भी जमीन दी जा चुकी है। इन दोनों संस्थान से रक्षा क्षेत्र में निवेश और छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में मदद मिलेगी।

बाजार में लौटने लगी मांग

उद्योग और बाजार दोनों अब कोरोना से उबर चुके हैं। उत्पादन भी बढ़ा है। उद्यमी इस सबसे राहत महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन, मंदी आदि वजहों से हुए नुकसान की भरपाई वे कर पा रहे हैं। उस समय रोजगार भी छिने थे। अब उद्यमों में रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। ऐसा उत्पादन बढ़ने के साथ मांग बढ़ने की वजह से संभव हो सका है।

- आरके शरण, सीईओ, एसोचैम यूपी-यूके

उत्पाद बेचने को बाजार भी दे रहे

लखनऊ को औद्योगिक जिला बनाने की योजना के पीछे अधिक से अधिक छोटी-छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए जाने की सोच है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी निवेश जाएगा। इस तरह की यूनिट को बड़ी दिक्कत यह होती है कि उन्हें बाजार नहीं मिल पाता, जहां वे अपने उत्पादों को बेच सकें। इसके लिए रास्ता निकाला गया कि बड़े उद्यमी अपनी जरूरत का कच्चा माल या उत्पाद यहां तैयार करा लें। ऑनलाइन-ऑफलाइन प्लेटफार्म का उपयोग भी सामान बेचने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। कई प्रमुख कंपनियों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। जल्दी ही इसे मूर्तरूप भी दिया जाएगा।

- सूर्यपाल गंगवार, डीएम

उद्योगों के विस्तार पर काम शुरू

लखनऊ में कई उद्योगपति अलग-अलग सेक्टर में अपने उद्योग के विस्तार की योजना पर काम शुरू कर चुके हैं। इसके आकार का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसके लिए जरूरी मशीनों की आपूर्ति की छह महीने से अधिक की वेटिंग निर्माताओं के पास है। इतना ही नहीं जीएसटी का बड़ा कलेक्शन भी इसका उदाहरण है। लखनऊ में पावर सेक्टर, हार्डवेयर के अलावा अब डिफेंस सेक्टर के लिए जरूरी उत्पाद बनाने के उद्योगों के विस्तार या नई यूनिट लगाए जाने पर काम चालू है। आने वाले तीन से पांच साल केअंदर नए उद्योग लखनऊ में दिखने लगेंगे।

- विनम्र अग्रवाल, चेयरमैन, सीआईआई